कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा की स्थिति:एक अध्ययन

डॉ. हरप्रीत कौर
सहायक प्रोफेसर एस. एस. जे. सुबोध टी.
टीकॉलेज, जयपुर, राजस्थान
harpreetkaur2011@gmail.com

सारांष

शोध-सार : विविधतापूर्ण संस्कृति वाले सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश को स्वतंत्र हुए पिचहत्तर वर्ष पूर्ण हो गए हैं। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाने के साथ साथ भारतीयों ने गुलामी का मुख्य कारण देश में शिक्षा का निम्न स्तर माना। ऐसा माना जाने लगा कि केवल शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जो भारतीय संस्कृति की संपोषक तथा वाहक है अतः तब से लेकर आज तक विभिन्न योजनाओं और नीतियों द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार व विकास करने के प्रयास जारी है। भारत जैसे विकासशील देश में भी कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए व सामाजिक दूरी को बढ़ाने के उद्देश्य से उद्योग धंधों व शिक्षण संस्थानों पर तालाबंदी कर दी गई। बंद शिक्षण संस्थान, शिक्षा की निरंतरता में बाधा के रूप में सरकार के समक्ष चुनौती बन कर खड़ी हो गयी। ना सिर्फ भारत में अपितु कोरोना वायरस ने विश्व के करीब 200 देशों की शिक्षा व्यवस्था को झकझोर दिया, जिस कारण औपचारिक शिक्षा असमंजस की स्थिति में दिखाई देने लगी। अचानक हुई तालाबंदी के कारण भारतीय कक्षा कक्षों में चल रही पारंपरिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का स्थान अनियोजित ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली ने ले लिया। अल्प तकनीकी ज्ञान, अल्प संसाधनों के साथ ऑन लाइन शिक्षा पद्धति को भी सभी अपनाने पर मजबूर हो गये। वर्तमान में सीमित तकनीकी संसाधनों के अभाव में अकस्मात रूप से पूर्णत: वर्चुअल लर्निंग मोड़ पर शिक्षा प्रदान करना विशाल जनसंख्या वाले भारत में कल्पना मात्र है। आने वाले समय में भारतीय प्रशासन को शिक्षा में सुधार के लिए सजग होकर कदम उठाने पड़ेंगे जिसमें सबसे प्रमुख शिक्षा में तकनीकी साधनों को बढ़ाना होगा, स्कूली बच्चों के समग्र विकास के लिए सूचना संचार तकनीकी को शिक्षा में अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा। तभी हमारा देश विश्व गुरु के रूप में सम्पूर्ण विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम होगा।

बीज-शब्द : वैश्विक महामारी, कोरोना काल, शिक्षा, शैक्षिक व्यवस्था की स्थिति

उद्देश्य-

प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्न उद्देश्य हैं–

१) कोरोा काल में ऑन लाइन शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना।

२) कोरोना महामारी के दौरान विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर शिक्षा व्यवस्था की स्थिति का अध्ययन करना।

संबंधित साहित्य-

प्रस्तुत शोध पत्र में कोरोना काल के दौरान शिक्षा की स्थिति और शैक्षणिक व्यवस्था पर कोरोना के प्रभाव का अध्ययन किया गया है जिसके अंतर्गत वैश्विक महामारी के दौरान भारत

तथा विदेशों में हुए विभिन्न सर्वेक्षणों का अध्ययन किया गया है जिसमें प्रमुख हैं–कोविड नाइंटीन पैंडमिकरू इम्प्लिकेशन ऑफ स्कूल क्लोजर ऑन द चिल्ड्रन इन इंडिया, इंडिया केस स्टडी बाई यूनेस्को, ह्यूमन राइट्स वॉच मई 2021, ऑक्सफैम इंडिया स्टेटस रिपोर्ट गारमेंट ऐंड प्राइवेट स्कूल ड्यू रिंग कोविड नाइनटीन इत्यादि का अध्ययन किया गया है।

शोध विधि-प्रस्तुत शोध पत्र गुणात्मक विधि पर आधारित है।

विविधतापूर्ण संस्कृति वाले सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश को स्वतंत्र हुए पिचहत्तर वर्ष पूर्ण हो गए हैं। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाने के साथ साथ भारतीयों ने गुलामी का मुख्य कारण देश में शिक्षा का निम्न स्तर माना। समाज का जो वर्ग शिक्षित था वह पूर्ण रूप से अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का दास बन चुका था। स्वतंत्रता पश्चात सरकारों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता महसूस की। ऐसा माना जाने लगा कि केवल शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जो भारतीय संस्कृति की संपोषक तथा वाहक हैअतः तब से लेकर आज तक विभिन्न योजनाओं और नीतियों द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार व विकास करने के प्रयास जारी है।

शिक्षा सबके लिए के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए पिछले 70 वर्षों में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान लागू किया गया, समाज के सभी वर्गों को शिक्षित करने के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए गए, बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए सरकारों द्वारा समय समय पर अनेक कार्यक्रम चलाए गए। इस समय अंतराल में हालाँकि निरक्षरता को पूर्णत: तो समाप्त नहीं किया जा सका ,लक्ष्य की ओर बढ़ने की हमारी गति मन्द तो जरूर थी परंतु हम पूर्ण साक्षर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत् रहे। ऐसे समय में वैश्विक आपदा के रूप में जनवरी 2020 से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने दस्तक दी और सम्पूर्ण विश्व के देशों में 10 मार्च से 25 मार्च 2020 तक पूर्ण तालाबंदी की नौबत आ चुकी थी। भारत जैसे विकासशील देश में भी कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए व सामाजिक दूरी को बढ़ाने के उद्देश्य से उद्योग धंधों व शिक्षण संस्थानों पर तालाबंदी कर दी गई। आकस्मात हुई इस बंदी ने ना सिर्फ अर्थव्यवस्था को तार तार कर दिया बल्कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की भी बखिया उधेड़ दी। बंद शिक्षण संस्थान, शिक्षा की निरंतरता में बाधा के रूप में सरकार के समक्ष चुनौती बन कर खड़ी हो गयी। ना सिर्फ भारत में अपितु कोरोना वायरस ने विश्व के करीब 200 देशों की शिक्षा व्यवस्था को झकझोर दिया, जिस कारण औपचारिक शिक्षा असमंजस की स्थिति में दिखाई देने लगी।संपूर्ण भारतमें एक सरकारी घोषणा मात्र से करोड़ों छात्रों के विद्यालय की ओर बढ़ते हुए कदमों को अचानक रोक दिया गया जिससे सभी राज्यों, जाति, लिंग व वर्गों के बच्चे घर में कैद हो गए। यूनिसेफ के एक अध्ययन के अनुसार विद्यालयों के बंद होने से पूर्व प्राथमिक व उच्च माध्यमिकस्तरके 246 मिलियन छात्र शिक्षा से वंचित हो गए, जिसमें 48प्रतिशत लड़कियाँ है।

अचानक हुई तालाबंदी के कारण भारतीय कक्षा कक्षों में चल रही पारंपरिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का स्थान अनियोजित ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली ने ले लिया। इस शिक्षण प्रणाली के लिए न तो प्रशासन की पूर्व तैयारी थी,न ही शिक्षकों की और न ही विद्यार्थियों की । असमंजस की स्थिति में चूँकि शिक्षा व्यवस्था की चरमराई दीवारों को बचाने का ऑन लाइन शिक्षा के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अल्प तकनीकी ज्ञान, अल्प संसाधनों के साथ ऑन लाइन शिक्षा पद्धति को भी सभी अपनाने पर मजबूर हो गये। शीघ्र ही अप्रैल 2020 में शिक्षा मंत्रालय ने अपने अल्टरनेटिव अकैडमिक कैलेंडर (ए ए सी) द्वारा शिक्षा को ऑनलाइन करते हुए नये दिशा निर्देश समस्त शिक्षण संस्थानों को प्रदान किये। समस्त राज्यों में शिक्षण संस्थाओं में असमानताएँ, शिक्षकों की संख्या व तकनिकी साधनों के रूप में पाई गई। इन सबके चलते सरकार ने तुरंत प्रभाव से शिक्षण योजनाओं में परिवर्तन किया जिसके अंतर्गत बच्चों को शिक्षा से जोड़ें रखने के लिए दूरस्थ स्थानों पर इंटरनेट की आसान पहुँच,बच्चों को स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि साधन उपलब्ध कराने के साथ साथ अधिक से अधिक डिजिटल पाठ्य वस्तु उपलब्ध कराने के प्रयास किये।हालाँकि यूनिसेफ रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में 12 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ग्रामीण जनसंख्या के केवल 32 प्रतिशत तथा शहरी जनसंख्या की केवल 54 प्रतिशत बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा है तथा भारतीय परिवार में केवल 11 प्रतिशत के पास डेस्कटॉप, लैपटॉप या टैबलेट जैसे उपकरण उपलब्ध है जो इस विशाल जनसंख्या वाले भारत देश में निश्चित रूप से अपर्याप्त है।इसके अतिरिक्त कोरोना संकट के दुष्परिणामों पर अर्थशास्त्री ज्यां ट्रेज व उनके साथियों ने स्कूली बच्चों के ऑनलाइन तथा ऑफलाइन शिक्षण पर 'स्कूल शिक्षण पर आपातकालीन' रिपोर्ट प्रस्तुत की और परिणाम स्वरूप निष्कर्ष निकाला कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में केवल 8प्रतिशत बच्चे ही ऑनलाइन मोड़ पर अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भागीदार है जबकि कोरोना के दौरान इस सुविधा के अभाव में 37 प्रतिशत बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं ।

यूनीसेफ की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कोरोना के दौरान छात्रों की सीखने की क्षमता पर प्रभाव का अध्ययन भारत के छह राज्यों बिहार, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल व उत्तर प्रदेश पर किया गया जिसमें यह निष्कर्ष प्राप्त हुए कि ऑनलाइन शिक्षण के कारण छात्र स्व अध्ययन पर अधिक समय लगा रहे हैं किन्तु अधिगम कम हो रहा है जबकि जब वह विद्यालय जाते हैं तो कम समय में अधिक सीख पाते हैं। अध्ययन से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि 97 प्रतिशत छात्र प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे ऑनलाइन शिक्षण अधिगममें लगाते हैं परंतु 3–4 घंटे की पढ़ाई, स्कूल की ऑफलाइन पढ़ाई से कम है। इसके अतिरिक्त कक्षा में समूह के साथ रहकर सीखना,सीखने के प्रति रुचि और उत्कंठा को बढ़ाता है। घर पर वह एकल वातावरण में नीरसता का अनुभव करता है इसके अतिरिक्त यूनिसेफ सर्वे इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के निष्कर्ष के अनुसार कुछ अभिभावक व माता पिता मानते हैं कि 5–13 वर्ष के 73प्रतिशत तथा 14 –18 वर्ष के 80 प्रतिशत विद्यार्थी स्कूल में जितना सीख पाते हैं उसकी तुलना में ऑनलाइन अधिगम में

उतना नहीं सीख पाते हैं। इसके अतिरिक्त 67प्रतिशत शिक्षक मानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षण के कारण बच्चे अपनी कक्षा से पिछड़ रहे हैं जिसने सर्वाधिक प्राथमिक स्तर को प्रभावित किया है।

अजीम प्रेमजीविश्वविद्यालय द्वारा पाँच राज्यों के 44 जिलों में एक शोध अध्ययन में विद्यार्थियों केसीखने की क्षमता कम होने के प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त किए तथा यह तथ्य सामने आया है कि बच्चों में बुनियादी ज्ञान,अवबोध तथा कौशलजैसे मुख्य अधिगम अनुभवों में पिछड़ापन बढ़ रहा है। 92 प्रतिशत बच्चे अपनी किसी एक भाषा में पिछड़ रहे हैं तथा 82 प्रतिशत बच्चों में गणितीय योग्यता का हानि हो रही है और गणित के सरल सवाल करने में वह पिछड़ रहे हैं।

एक अन्यशोध द्वारा चौंकाने वाला तथ्य यह भी सामने आया है कि दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा होने के बावजूद 40 प्रतिशत विद्यार्थियों ने ऑनलाइन शिक्षण का लाभ नहीं उठाया क्योंकि वह ऑनलाइन शिक्षण यंत्रों या उपकरणों का उपयोग करना ही नहीं जानते थे और इन क्षेत्रों में 73 प्रतिशत विद्यार्थी जागरूकता के अभाव में शिक्षा से वंचित हो गए हैं। हमारे देश में कोरोना काल में बच्चों का शिक्षा से वंचित होने का मुख्य कारण ऑन लाइन शिक्षा के लिए तकनीकी या प्रौद्योगिकी की उपलब्धता का कम होना है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2014 के आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में केवल 27 प्रतिशत परिवार ही ऐसे हैं जिनके किसी सदस्य के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है इनमें 47 प्रतिशत ऐसे परिवार हैं जिनकेपास इंटरनेट की सम्बद्धता तो संभव है परंतु इंटरनेट संबद्धता स्थापित करने के लिए तकनीकी उपकरण जैसे लैपटॉप कंप्यूटर या अन्य उपकरण उपलब्ध नहीं है। भारत में 12.5 प्रतिशत छात्रों के परिवार इंटरनेट का उपयोग करते हैं जिसमें ग्रामीण परिवार केवल 5 प्रतिशत तथा शहरी परिवार 27 प्रतिशत इंटरनेट की सुविधाका लाभ उठा रहे हैं और वर्तमान में सीमित तकनीकी संसाधनों के अभाव में अकस्मात रूप से पूर्णत: वर्चुअल लर्निंग मोड़ पर शिक्षा प्रदान करना विशाल जनसंख्या वाले भारत में कल्पना मात्र है। इस संदर्भ में माता पिता के दो समूहों में भी काफी अंतर देखने को मिला। यूनीसेफ सर्वे "The Potential of Online Learning Resources and Awareness Towards Them" में अभिभावकों ने ऑनलाइन कक्षा में अध्ययन के लिए एक मुख्य समस्या यह बताई कि वे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना तो चाहते हैं परंतु तकनीकी उपकरण खरीदने में आर्थिक रूप से अक्षम है। वहीं एक अन्य समूह के अभिभावक अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षण के लिए उपकरण तो उपलब्ध कराने में सक्षम है परंतु उनमें पर्याप्त जागरूकता की कमी है।

यूनेस्को द्वारा किए गए सर्वे में बताया गया है कि 2020 में करीब नौ महीने बीत जाने के बाद कई देशों की सरकारों ने दूरस्थ शिक्षा की पेशकश की है। सर्वे के अनुसार लगभग एक चौथाईदेशजो निम्न आय वाले थे उन्होंने इस कोरोना काल में शिक्षा की कोई निगरानी नहीं की। संचार की कमी के कारण ऑनलाइन कक्षा में बच्चों की उपस्थिति दर्ज ही नहीं हुई।इसी कारण कई देशों के स्कूलों का लगभग 9 से 11 महीने तक विद्यार्थियों सेकोई संपर्क नही रहा।

इसी समय अंतराल में विद्यार्थियों में आयु बढ़ने के साथ नि शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यार्थी को शिक्षा अर्र्जन की हानि हुई है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के लगभग 44 देश अपने कानूनी ढांचे में कम सेकम ग्यारह वर्ष तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देते हैं जिसमें भारत शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है।कोरोना काल में विद्यालय बंद होने के कारण बच्चे आयु निकलने के कारण निःशुल्क शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाये है इसके अतिरिक्त कम से कम 13 देशों में विद्यार्थी को 6 वर्ष तक की नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है इसके दो वर्ष के समय में छह वर्ष की न्यूनतम शिक्षा का लाभ नहीं ले पाएंगे।

स्कूली बच्चों के माता पिता पर एक अन्य अध्ययन किया गया जिसमें यह बात सामने आयी है कि 49 प्रतिशत निजी विद्यालयों के द्वारा महामारी के दौरान शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था की नहीं दी गई थी और एक अन्य सर्वे में पब्लिक स्कूलों के लिए भी कुछ ऐसा ही तथ्य सामने आया कि 90 प्रतिशत पब्लिक स्कूल ऑन लाइन शिक्षा व्यवस्था करने में पूर्ण रूप से असमर्थ रहे।

स्वतंत्रता से अब तक भारत ने बहु आयामी सामाजिक व आर्थिक प्रगति की। कई वर्षों से भारत की विकास दर विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी उच्च रही। यद्यपि कोरोना काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हुई परंतु इसके पश्चात मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों को अपनाए जाने से अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के प्रयास जारी हैं। कोरोना काल मेंविश्व के सभी देशों के वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन की खोज में लगे हुए थे तब भारत के प्रयास भी अभूतपूर्व रहे। यदि शिक्षा की बात करें तो भारत में शिक्षा का स्तर सुधारने के प्रयास कोरोना काल पूर्व से ही चल रहे थे। यदि हम कहें कि भारत में शिक्षा का संकट महामारी से पहले ही विकट था तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। महामारी के कारण शिक्षा पर संकट और गहरा गया। उपरोक्त अध्ययनों से पता लगता है कि कोरोना काल में भारतीय शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई।

अचानक आयी इस आपदा ने भारतीय सरकार व प्रशासन कोभविष्य के लिए नई सीख दी।आने वाले समय में भारतीय प्रशासन को शिक्षा में सुधार के लिएसजग होकर कदम उठाने पड़ेंगे जिसमें सबसे प्रमुख शिक्षा में तकनीकी साधनों को बढ़ाना होगा, शिक्षकों के लिए ई अधिगम के साधन उपलब्ध कराए जाएं और उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, इंटरनेट तकनीक में सुधार व दूरस्थ स्थानों पर इंटरनेट सम्बद्धता को बढ़ाना,ई अधिगम के उद्देश्यों तथा उसकी प्रभावशीलता को बढ़ावा देना ,स्कूली बच्चों के समग्र विकास के लिए सूचना संचार तकनीकी को शिक्षा में अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा।तभी हमारा देश विश्व गुरु के रूप में सम्पूर्ण विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम होगा।

References:

- Covid 19 pandemic: Implication of school closure on children in India – The BMJ accessed December 2020.
- Human Right Watch May 2021: "Years don't wait for them", Increased inequalities in Children's Right to Education due to COVID-19 Pandemic.
- India Case study by UNESCO: Situation analysis on the effects of and responses to COVID-19 on the education sector in Asia.
- Oxfam India Status Report, Government and private schools during COVID-19, 4 September 2020.
- Times Now Digital कोरोना काल में शिक्षा हुई प्रभावित Jan 31, 2022.